

आईपीएस अजय
भट्टानगर बने सीबीआई
के विशेष निदेशक

रांची। झारखण्ड कैडर के 1989 वेच के भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के वरिष्ठ अधिकारी

अजय भट्टानगर को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) में विशेष निदेशक नियुक्त किया गया है। भट्टानगर फिल्म लंबी आईपीएस के वरिष्ठ अधिकारी

में कहा गया है कि उन्हें 20 नवंबर 2024 को उनकी

सेवानिवृत्ति की तारीख तक इस

पद पर नियुक्त किया गया है।

सीबीआई में सुरक्षा निदेशक

अनुराग अब एंजी में अतिरिक्त

निदेशक होंगे। उन्हें 24 जूलाई 2023 को विशेष अधिकारी के लिए नियुक्त किया गया है।

चाईबासा : माओवादियों

का पूर्वी क्षेत्रीय मुख्यालय

हुआ ध्वस्त

चाईबासा। माओवादियों के पूर्वी क्षेत्रीय मुख्यालय को सुरक्षाकालों ने ध्वस्त कर दिया है। पश्चिमी सिंधूभूमि जिले के टोटो थाना क्षेत्र के सर्जोमुखुरु में माओवादियों ने अपना ईस्टन रीजनल हेडकार्टर बना रखा था और यहां तक पहुंचने के लिए वित्त जनवरी महीने से जिला गुरुवार और तमाम केंद्रीय सुरक्षा बलों ने सुरक्षा अधिकारी आशुतोष शेखर ने बुधवार को चाईबासा में इसे पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी बताया।

रोहित झा हत्याकांड में

दो गिरफ्तार

रांची। चूटिया थाना क्षेत्र के स्टेनल रोड स्थित सरकारी बस डिपो के समीप आंदो चालक रोहित झा वर्ष पहिले हत्या मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में संतोष साह और एक अन्य शामिल हैं। दोनों से पूछताल की जा रही है। बताना जा रहा है कि बुधवार को अहले सुवह सिटी डोस्ट्स लैंबर कुमार और चूटिया थाना प्रभारी सह इंसेक्टर वैक्टेस कुमार ने दलबल के साथ बूटी मोड़ में छापेमारी कर संतोष और एक अन्य को गिरफ्तार किया है।

लोहरदगा आवासीय

विद्यालय की छात्राओं ने

थाईलैंड में दिखाया दम

लोहरदगा। थाईलैंड में

अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता

खेलों में गोली लोहरदगा जिले की

बच्चियों की जिले और राज्य

समेत पूरे देश का मान खाली है।

लोहरदगा जिले में कस्तूरबा गांधी आवासीय और झारखण्ड बालिका आवासीय विद्यालय की बच्चियों ने थाईलैंड भारत की ओर से खेलों हुए 4 खण्ड पदक जीते हैं।

जिलेता टीम की खिलाफ पहुंचे।

जिलों को लोहरदगा 30

जून को लोहरदगा पहुंचे।

बिरसा मुंडा एयरपोर्ट

विस्तारीकरण में गबन

के आरोपी को राहत नहीं

रांची। रांची बिरसा मुंडा

एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के

लिए जिमीन के बलाले फर्जी

तरीके से 20 लाख से अधिक

मुआवजा राशि भुगतान प्राप्त

करने के मामले के आरोपित

पदाधिकारी और योजना सह

वित्त विभाग के तकलीफीन

रांची एयरपोर्ट विद्यालय में निजी सहायक के पद पर

प्रतिनियुक्त हैं। सरकार ने उनके

अपील अध्यादेश को खारिज

कर दिया है। साथ ही उन्हें दिए

गये दंड को यथावत रखा है।

इस संबंध में बुधवार को

कार्यक्रम विभाग ने अधिकारी

जारी कर दी है।

कैबिनेट : केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम प्रणाम योजना को मंजूरी दी



राज्यसी। नई दिल्ली
बुधवार के भारतीय प्रधानमंत्री की अधिकारी द्वारा देखी गयी विशेष निदेशक है। अदेश में कहा गया है कि उन्हें 20 नवंबर 2024 को उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख तक इस पद पर नियुक्त किया गया है। उन्हें मंजूरी दी गयी विभाग निदेशक है।

सीबीआई में सुरक्षा निदेशक

अनुराग अब एंजी में अतिरिक्त

निदेशक होंगे। उन्हें 24 जूलाई

2023 को विशेष अधिकारी के लिए नियुक्त किया गया है।

सीबीआई : माओवादियों

का पूर्वी क्षेत्रीय मुख्यालय

हुआ ध्वस्त

चाईबासा। माओवादियों के पूर्वी

क्षेत्रीय मुख्यालय को सुरक्षाकालों

द्वारा ध्वस्त कर दिया गया है।

पश्चिमी सिंधूभूमि जिले के टोटो थाना क्षेत्र

के सर्जोमुखुरु में माओवादियों ने

अपना ईस्टन रीजनल हेडकार्टर

बना रखा था और यहां तक

पहुंचने के लिए वित्त जनवरी

महीने से जिला गुरुवार और तमाम

केंद्रीय सुरक्षा बलों ने सुरक्षा

अधिकारी आशुतोष शेखर ने

बुधवार को चाईबासा में अधिकारी

प्रधानमंत्री ने कहा कि जो ग्राम

परिवारों के प्रधानमंत्री ने कहा कि जो ग्राम</p

डीसी की अध्यक्षता में जिला योजना कार्यकारिणी समिति की बैठक योजनाओं को समय पूरा करें : डीसी

नवीन मेल संवाददाता

रामगढ़। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 के तहत बुधवार को उपायुक्त सह अध्यक्ष जिला योजना कार्यकारिणी रामगढ़ माध्यमी नियम की अध्यक्षता में समाहरणालय सभाकक्ष में जिला योजना कार्यकारिणी समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान परियोजना निदेशक आत्मा प्रवीण कुमार द्वारा उपायुक्त एवं अन्य अधिकारियों को जानकारी दी गई कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 के तहत जल संवर्धन के उद्देश्य से रामगढ़ जिले में 5 वर्षों की योजना बनाई गई है जिसमें योजना के तहत अब तक



2 वर्ष पूरे हो चुके हैं। बैठक के दौरान उहोने योजना के तहत दुलमी प्रखंड के लगभग 5072 हेक्टेयर भूमि पर चेक

निर्माण, ट्रैक कम बंड, मेढ़बंदी, समुदायिक एवं अन्य तालाब निर्माण, मिशन अमृत सरोवर, मनरेगा सहित अन्य योजनाओं की जानकारी दी जिसके उपरांत

पर्यटन को बढ़ावा मिले

झारखण्ड अपने प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक महत्व के स्थलों के रूप में देश व विदेश में जाना जाता है। ऐसे स्थल रोजगार सृजन में अहम भूमिका निभा सकते हैं। बस जरूरत है, इसे संभाल कर रखने की। झारखण्ड के पलामू प्रमंडल में अवस्थित बेतला नेशनल पार्क, पलामू किला, मिरचीया फॉल, बूढ़ा बांध जैसे असंख्य स्थल हैं, जिन्हें पर्यटक स्थल के रूप में बढ़ा आकार दिया जा सकता है। अभी बरसात के शुरूआत में ही वर्षा होने के कारण बेतला पार्क में रौनक आ गयी है। ऐसे में दूर-दूर से पर्यटकों का आना शुरू हो गया है। प्रजनन का समय निकट आ जाने के कारण दो चार दिनों में नेशनल पार्क बंद होने वाला है। इसलिए इसकी खुबसूरती को कैमरे में कैद करने के लिए पर्यटकों की होड़ लगी है। दूसरी तरफ राज्य के पर्यटक विभाग ने साहिबगंज के बरहेट स्थिति सिंट्रो कानून जन्म स्थली को गार्जीय महत्व का पर्यटन

झारखण्ड के पलामू
प्रमंडल में अवस्थित
ला नेशनल पार्क, पलामू
किला, मिरचीद्या
फॉल, बूढ़ा बांध जैसे
भर्सांख्य स्थल हैं, जिन्हें
र्यटक स्थल के रूप में
बढ़ा आकार दिया जा
सकता है।

का घोर अभाव है। पर्यटन को बढ़ावा देकर राज्य की अर्थव्यवस्था को सुधारा जा सकता है। बहरहाल कई जगहों पर पर्यटन स्थल घोषित कर राज्य सरकार ने अच्छा कार्य किया है। अब जरूरत है राज्य के सबसे पिछड़े जिले पलामू प्रमंडल की ओर ध्यान देने की। कारण यहां कई ऐसे जगह हैं जिन्हें पर्यटन स्थल घोषित कर राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा सकता है। इसके बाद रोजगार सृजन की ओर ध्यान देने की जरूरत है। हस्तकला और हस्तशिल्प को भी इनके माध्यम से बढ़ावा दिया जा सकता है। ऐसे में ऐतिहासिक और प्राकृतिक स्थलों की सुरक्षा की जवाबदेही भी महत्वपूर्ण कड़ी है। सुरक्षा की दृष्टि से पर्यटकों को यह एहसास होना चाहिए कि वह अमुक जगह पर सुरक्षित हैं। बहरहाल यह बात कहने में कोई अतिशयेक्ति नहीं कि पर्यटन को बढ़ावा देकर जहां एक ओर राज्य की बिगड़ी स्थिति को सुधारा जा सकता है, वहाँ हस्तकला और हस्तशिल्प के माध्यम से अपने होने का प्रमाण पूरी दुनिया में झारखंड दे सकता है। जिसका नजारा पिछले दिनों अमेरिका में देखने को मिला। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने यहां के प्रेसिडेन्ट को झारखंड के बने तसर सिल्क साल को भेंट किया। इसके गहरे अर्थ हैं, बस समझने की जरूरत है। ऐसे में सहज समझा जा सकता है कि यहां की बनी चीज का विदेशों में भी गहरी मांग है। दूसरी तरफ झारखंड में सब कुछ होने के बाद भी यहां के लोगों को राजरी रोजगार के लिए अन्य जगहों पर भटकना पड़ता है। तमाम प्राकृतिक संसाधनों के बीच यहां की कोख में गरीबी और लाचारी देखने को मिलती है। ऐसे में सरकार को इन चीजों को फोकस कर संसाधनों को बढ़ाने में मदद लेनी चाहिए। यह सब दृढ़ इच्छा शक्ति से संभव है। कारण यहां संसाधनों की कोई कमी नहीं है। बस जरूरत है उसे मुख्य धारा में शामिल कर देना। राज्य कई पर्यटन स्थल हैं जो आज भी जीर्णद्वारा की प्रतीक्षा में हैं। इनके दिन बहुर जाने के बाद असीम संभावनाएं दिखती हैं। ऐसे में पर्यटन को एक नया आयाम मिल जाने से कोई नहीं रोक सकता है। बस जरूरत है उसे अमलीजामा पहनाने की।

कांग्रेस व क्षेत्रीय दलों में दांवपेंच का खेल जारी

आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा को सत्ता से बेदखल करने की रणनीति बनाने के लिए कुछ राजनीतिक दलों की पटना में महाबैठक हो चुकी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बुलावे पर जुटे 15 दलों के नेताओं ने इस बैठक में विपक्षी एकता के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने की बात कही है। मगर भाजपा विरोधी दलों के ये दावे बैठक खत्म होने से पहले ही हवा हो गये। दिल्ली में अधिकारियों की नियुक्ति और स्थानांतरण को लेकर लाये गये केंद्र सरकार के अध्यादेश के विरोध का कंग्रेस की ओर से ठोस आश्वासन न मिलने से खफा आम आदमी पार्टी बैठक के बाद आयोजित पत्रकार वार्ता से नदारद रही। बैठक के चंद घंटे बाद ही पश्चिम बंगाल कंग्रेस के अद्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी पर तीखे हमले किये तो ममता बनर्जी ने भी एक बार फिर कंग्रेस और माकपा पर भाजपा से मिलीभगत का आरोप मढ़ा। बैठक के बाद से हो रही बयानबाजी से स्पष्ट है कि भले ही कंग्रेस और क्षेत्रीय दलों के नेता विपक्षी एकता की बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हों लेकिन उनका असल मकसद एक-दूसरे को विपक्षी एकता में बाधक साबित करके भाजपा का मददगार दिखाना ज्यादा लग रहा है। ताकि भाजपा विरोधी मुस्लिम मतदाताओं पर पकड़ ज्यादा मजबूत की जा सके। लगातार दो आम चुनाव में भाजपा की प्रचंड विजय ने विरोधियों की नींद हराम कर दी है। राजनीतिक विशेषकों के साथ-साथ अब तमाम नेता भी सार्वजनिक तौर पर यह स्वीकार करने लगे हैं कि भाजपा के विजय रथ को अकेले रोक पाने के क्षमता किसी भी विपक्षी दल में नहीं है। इसीलिए भाजपा के खिलाफ हर सीट पर विपक्ष का संयुक्त उमीदवार उतारने की बात की जा रही है। लेकिन इस विपक्षी मोर्चे की कमान किसके हाथ में होगी इसको लेकर मोदी विरोधियों में गहरे मतभेद हैं। गैर भाजपा दलों में कंग्रेस ही एक मात्र पार्टी है जिसका पूरे भारत में संगठन मौजूद है। इसलिए कंग्रेसियों का मानना है कि विपक्षी एकता की कमान स्वाभाविक तौर पर कंग्रेससे को मिलनी चाहिए। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में शानदार जीत के बाद से कंग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं का मनोबल काफी बढ़ा हुआ है। उन्हें लगता है कि हिमाचल प्रदेश के बाद कर्नाटक में भाजपा को सत्ता से बेदखल करने के बाद मोदीवाले विरोधी गठबंधन के नेतृत्व को लेकर उसकी दावेदारी मजबूत हुई है। ठीक इसके उलट कर्नाटक के चुनावी नतीजे आते ही तमाम क्षेत्रीय दलों के नेताओं के माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई देने लगी हैं। वे पहले के मुकाबले ज्यादा आक्रामक तरीके से कंग्रेस पर हमलावर हैं। दरअसल लगभग सभी क्षेत्रीय दलों की राजनीति जिस मुस्लिम वोट बैंक पर टिकी हुई है उसमें कंग्रेस की सेंधमारी से ये दल घबराए हुए हैं। बीते 30 साल में जिन राज्यों में भी क्षेत्रीय दलों का विकास हुआ उसकी कीमत कंग्रेस को ही चुकानी पड़ी है। इन दलों ने किसी एक जाति के वोट बैंक को आधार

स पहल हा हधा हा नव

राजनीति

बनाकर उसके साथ मुस्लिम वोटर्स को जोड़कर सफलता हासिल कर्ना है। इस बार खास यह है कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने पहली बार क्षेत्रीय पार्टी जनता दल सेक्युरिटी के मुस्लिम वोट बैंक में सेधमारी करने में सफलता हासिल कर ली। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में साप्रदायिक मुद्दे काफी उफान पर थे। कांग्रेस ने मुस्लिमों को भरोसा दिया कि प्रदेश में उनकी सरकार बनने पर कश्ताओं में भी हिंजाव पहनने की इजाजत दे दी जाएगी।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की हाल ही में समाप्त हुई संयुक्त राज्य अमेरिका यात्रा इस अर्थ में ऐतिहासिक है कि इसने अपने बाले वर्षों के लिए भारत को एक प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित कर दिया है। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका प्रौद्योगिकी संचालित समान सहयोग के युग में प्रवेश कर रहे हैं और यह सहयोग उस यात्रा की शुरूआत का प्रतीक है, जिसके बारे में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है, 'आकाश ही सीमा नहीं है।' वास्तव में, इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को जाता है, जिन्होंने पिछले 9 वर्षों के दौरान कई गैर-परंपरागत और नयी राह दिखाने वाले अभिनव निर्णय लिए, जिनकी वजह से भारत प्रमुख क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ने में सक्षम हुआ। उदाहरण के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसने भारत से कई वर्ष पहले अपनी अंतरिक्ष यात्रा की शुरूआत की थी, आज भारत को अपने भविष्य के प्रयासों में एक समान भागीदार के रूप में आमंत्रित करता है। 21 जून को वाशिंगटन स्थित विलार्ड इंटर-कॉन्टिनेंटल होटल में एक समारोह के दौरान, भारत आर्टेमिस समझौता पर हस्ताक्षर करने वाला 27वां देश बन गया। आर्टेमिस समझौता, शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए राष्ट्रों के बोच नागरिक अंतरिक्ष अन्वेषण सहयोग का मार्गदर्शन करने के लिए सिद्धांतों के एक व्यावहारिक समूह की स्थापना करता है। यह भारत को चंद्रमा और अन्य खगोलीय पिंडों की खोज के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाले आर्टेमिस कार्यक्रम में भाग लेने में सक्षम बनाता है। ध्यान देने योग्य है कि यह समझौता अंतरिक्ष क्षेत्र में, विशेषकर इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के आयात से जुड़े प्रतिबंधों में छूट देने का मार्ग प्रशस्त करेगा, जिससे भारतीय कंपनियों को अमेरिकी बाजारों के लिए प्रणाली विकसित करने और नवाचार करने में लाभ होगा। यह अन्य वैज्ञानिक कार्यक्रमों में भारत को संयुक्त रूप से भागीदार बनने की सुविधा प्रदान करेगा। मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रमों समेत विभिन्न गतिविधियों में दीर्घकालिक सहयोग के लिए सामान्य मानकों तक पहुंच की अनुमति देगा और मादको-इलेक्ट्रॉनिक्स क्वांटम

भारत व अमेरिका ने समान युग की शुरुआत की



डा. जितद्र स

सुदूर अंतरिक्ष मिशनों के लिए अरबों डॉलर की आवश्यकता होती है और इससे पूरी मानवता लाभान्वित होती है। इसलिए, यह जरूरी है कि राष्ट्र मानवता के लाभ के लिए अपने संसाधनों का उपयोग करें। बिना समय गंवाए, समान विचारधारा वाले देशों को आगे आना होगा, सहयोग करना होगा और एक-दूसरे के लाभ और अनुभवों पर काम करना होगा, जैसा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जोर देकर कहा है - 'हमें अलग-थलग होकर काम नहीं करना चाहिए!'। अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत-अमेरिका के बीच नये सहयोग का पहला बड़ा स्पष्ट लाभ देखने के लिए हमें शायद लंबे समय तक इंतजार नहीं करना होगा। अगले साल एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) भेजा जा सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ बैठक के बाद व्हाइट हाउस में इसकी पुष्टि कर चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदा यात्रा के दौरान भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के संयुक्त वर्तव्य में कहा गया है कि नासा अपने एक सुविधा केंद्र में भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को 'उन्नत प्रशिक्षण' प्रदान करेगा। दोनों पक्षों के समान, अन्य क्षेत्रों के लिए भी परस्पर लाभ में तेजी देखने को मिलेगी। अमेरिकी मेमोरी चिप कंपनी, माइक्रोन टेक्नोलॉजी, इंक ने गुरुवार को कहा कि वह भारत के गुजरात में एक नई चिप असेंबली और परीक्षण सुविधा इकाई के लिए 825 मिलियन डॉलर तक का निवेश करेगी, जो देश में इसकी पहली निर्णाय-इकाई होगी। केंद्र सरकार और गुजरात राज्य सरकार के सहयोग से इस सुविधा केंद्र में 2.75 बिलियन डॉलर का कुल निवेश किया जायेगा।

थे। विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते कांग्रेस चाहती है कि राहुल गांधी को नेता प्रोजेक्ट किया जाए। राजद नेता लालू यादव व तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन राहुल गांधी के पक्ष में खड़े हैं। ममता बनर्जी, शरद पवार, अरविंद केजरीवाल सामूहिक नेतृत्व की बात कर रहे हैं। पटना मीटिंग में शामिल इन नेताओं के हाथ तो जरूर मिले मगर अभी तक दिल नहीं मिल पाये हैं। अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली सरकार के खिलाफ लाये गये अध्यादेश के खिलाफ राज्यसभा में कांग्रेस को उनका समर्थन करने की बात कही। इस पर कांग्रेस अध्यक्ष मलिकार्जुन खड़गे व अरविंद केजरीवाल में बहस भी हुई। खड़गे ने कहा कि हम ऐसा कोई वादा नहीं कर सकते हैं। हमारी पार्टी के मंच पर इस बाबत चर्चा करके फैसला लिया जायेगा। केजरीवाल ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि राज्यसभा में कांग्रेस उनकी सरकार के खिलाफ लाए गये अध्यादेश के खिलाफ मतदान नहीं करेगी तो भविष्य में वह किसी भी विपक्षी गठबंधन की बैठक में शामिल नहीं होगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कांग्रेस द्वारा उनकी सरकार के खिलाफ चलाये जा रहे आंदोलन को लेकर नाराजी जताई। ममता का कहना है कि पश्चिम बंगाल में उनकी सरकार अच्छा काम कर रही है। कांग्रेस जानबूझकर उनको बदनाम करने के लिए लगातार आंदोलन कर सरकार की छवि खराब कर रही है। कांग्रेस को अपने प्रादेशिक नेताओं को उनकी

“समय बहाकर ले जाता है
नाम और निशान,
कोई ‘हम’ में रह जाता है कोई



रमेश सर्गफ धमो

पटना की बैठक में
शामिल 15 दलों की देश
के 11 प्रदेशों में सरकार
है। पिछले नौ साल में
पहली बार यह दल एक
मंच पर आये हैं। पटना में
जुटे 15 दलों के लोकसभा
में 112 सामाजिक हैं।

दिल भी मिलें तो बने बात, विपक्षी दलों का दलदल

रमेश सर्फ धमोरा

पटना की बैठक में शामिल 15 दलों की देश के 11 प्रदेशों में सरकार है। पिछले नौ साल में पहली बार यह दल एक मंच पर आये हैं। पटना में जुटे 15 दलों के लोकसभा में 142 सदस्य हैं। यह कुल लोकसभा सदस्यों का 26 प्रतिशत है। राज्यसभा में इन दलों के 94 सदस्य हैं। यह 38 प्रतिशत है। राज्यों की विधानसभाओं की कुल 4123 सीटों में से 1717 इन 15 दलों के पास है। यह कुल विधानसभा सदस्यों का 42 प्रतिशत है। कांग्रेस की देश के चार प्रदेशों राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक में सरकार है। कांग्रेस के पास लोकसभा में 49, राज्यसभा में 29 व विभिन्न प्रदेशों की विधानसभाओं में 725 सदस्य हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को कुल 11 करोड़ 94 लाख 95 हजार 214 वोट मिले थे। विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते कांग्रेस चाहती है कि राहुल गांधी को नेता प्रोजेक्ट किया जाए। राजद नेता लालू यादव व तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन राहुल गांधी के पक्ष में खड़े हैं। ममता बनर्जी, शरद पवार, अरविंद केजरीवाल सामूहिक नेतृत्व की बात कर रहे हैं। पटना मीटिंग में शामिल इन नेताओं के हाथ तो जरूर मिले मगर अभी तक दिल नहीं मिल पाये हैं। अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली सरकार के खिलाफ लाये गये अध्यादेश के खिलाफ राज्यसभा में कांग्रेस को उनका समर्थन करने की बात कही। इस पर कांग्रेस अध्यक्ष मलिकार्जुन खड़गे व अरविंद केजरीवाल में बहस भी हुई। खड़गे ने कहा कि हम ऐसा कोई वादा नहीं कर सकते हैं। हमारी पार्टी के मंच पर इस बाबत चर्चा करके फैसला लिया जायेगा। केजरीवाल ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि राज्यसभा में कांग्रेस उनकी सरकार के खिलाफ लाए गये अध्यादेश के खिलाफ मतदान नहीं करेगी तो भविष्य में वह किसी भी विपक्षी गठबूँधन की बैठक में शामिल नहीं होंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कांग्रेस द्वारा उनकी सरकार के खिलाफ चलाये जा रहे आंदोलन को लेकर नाराजगी जताई। ममता का कहना है कि पश्चिम बंगाल में उनकी सरकार अच्छा काम कर रही है। कांग्रेस जानबूझकर उनको बदनाम करने के लिए लगातार आंदोलन कर सरकार की छवि खराब कर रही है। कांग्रेस को अपने प्रादेशिक नेताओं को उनकी

